1967-68 की आर्थिक समीक्षा

I. प्रस्तावना

मई, 1967 में पेश की गयी 1966–67 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया था कि पिछले लगातार दो वर्षों से कृषि उत्पादन में कमी होने से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। बाद की सूचना से पता लगा कि 1965-66 में राष्ट्रीय आमदनी में जो कमी हुई थी वह उससे कुछ अधिक थी जिसका हिसाब पहले लगाया गया था और 1966-67 में जो सुधार हुआ वह सीमान्तिक था (देखिये सारणी 1)। हालांकि अन्न के उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि हुई, लेकिन 1966–67 में कुल कृषि उत्पादन पहले के वर्ष के मुकाबले कुछ कम रहा। 1966–67 में औद्योगिक उत्पादन में बहुत धीरे-धीरे वृद्धि हुई और उसके बाद की अवधि के क्रियाकलाप की गति में उल्लेखनीय तीव्रता नहीं आयी। वस्तुओं का उत्पादन कम होने के कारण परिवहन और अन्य सेवाओं के लिए पैदा होने वाली मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2. 1967–68 की सब से आकर्षक घटना यह रही कि अनुकूल वर्षा वाले वर्ष में कृषि के विकास के लिए जिस नयी योजना को अमल में लाया गया उस के कारण कृषि-उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इससे पहले के वर्षों में मौसम खराब रहने के कारण, खेती के काम की चीजों की अधिक मात्रा में उपलब्धि होने के बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ सका था। वर्ष भर में, सब मिला कर राष्ट्रीय आय में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन वर्ष के ज्यादातर हिस्से में नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि बिहार जैसे इलाकों में, जिनमें अनाज का खास तौर पर तोड़ा है, पर्याप्त मात्रा में अन्न की सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय और वहां की जनता में अन्न खरीदने की शक्ति फिर से पैदा की जाय तथा सारे देश में सरकारी अभिकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में अन्न का समुचित वितरण करने का काम जारी रखा जाय। दुर्भिक्ष-निवारण का कुल प्रशासनीय काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अन्न और सामान्य कृषि वस्तुओं के अभाव के परिणामस्वरूप होने वाली मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए राजस्व और मुद्रा संबंधी नीतियों को अमल में लाया गया। वर्ष के अन्त में, अन्न के मूल्य कम हुए, क्योंकि मंडियों में फसल का अनाज काफी मात्रा में आना शुरू हो गया था। खेती से मिलने वाले कच्चे माल की कमी के कारण और आंशिक रूप में, मांग की कमी के कारण, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति धीमी पड़ गयी थी। मुद्रा बाहुल्य यानी सिक्के के फैलाव को नियंत्रित रखने की व्यापक नीति का ठीक तरह से पालन करते हुए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ खास उपायों को अमल में लाया गया। वर्ष के अन्तिम भाग में, कृषि के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण, औद्योगिक उत्पादन में भी थोड़ी वृद्धि

हुई । ऋण-परिशोधन (डैट-सर्विसिंग) सेवाओं और ऐसी आयात संबंधी आवश्यकताओं के कारण जिनके लिए धन की व्यवस्था विदेशी सहायता से न की जा सकी, शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट्स) पर बराबर दबाव बना रहा । ऋण-परिशोधन संबंधी अदायगियों के लिए पुनर्वित्त प्राप्त करने के मामले में भी कुछ प्रगति हुई । यद्यपि माल की सप्लाई कम होने के कारण निर्यात के रास्ते में रुकावट आयी, किन्तु निर्यात की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये, जिनमें कुछ निर्यात-शुल्कों का घटाया जाना भी शामिल है ।

3. विदेशों से मंगाये जाने वाले अनाज पर निर्भर रहना जल्दी से जल्दी कम हो जाय इसके लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य है । खेती-बाड़ी के काम आने वाली चीजों का प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन करने और जरूरी होने पर उन्हें बाहर से मंगाने की आवश्यकता रहेगी । इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि किसानों को काफी आमदनी होती रहे, अनाज की वसूली के मूल्यों में हेरफेर किया गया है। काफी मात्रा में अन्न प्राप्त करने और आयात से उस मात्रा की और अधिक पूर्ति करने के समुचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं, ताकि न केवल अन्न के वितरण की समुचित व्यवस्था बनी रहे, बल्कि अन्न के संकट-निरोधक भण्डार (बफर स्टाक) भी बनाये रखे जायें । संकट-निरोधक भण्डारों को बढ़ाने से विकास-कार्य में वृद्धि होगी, क्योंकि इससे मौसमों के प्रतिकूल असर से बचाव के एक साधन की व्यवस्था हो जायगी । आशा है कि अन्न का जो गैर-सरकारी भण्डार, पहले के दो वर्षों में कम हो गया था, अब फिर से बढ़ जायेगा । लेकिन सरकारी और गैर-सरकारी माल की मात्रा में होने वाली वृद्धि को हिसाब में लेने के बाद भी, अनाज की सप्लाई की स्थिति, जो हाल के पिछले दिनों की निस्बत तो अच्छी है, ऐसी रहेगी कि खाद्य स्थिति को बड़ी सावधानी से संभालने की जरूरत होगी । वाणिज्यिक फसलों की ज्यादा उपलब्धि का मतलब यह होना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जायेंगी ; और आशा है कि ज्यादा आमदनियों के कारण औद्योगिक उप-भोक्ता वस्तुओं की मांग फिर से उभर आयेगी । खाद्यान्न की विभिन्न जिन्सों और दूसरे कृषि-उत्पादों में अधिक निवेश के अलावा, हो सकता है कि बाजार की सुधरी हुई स्थिति और राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कारण गैर-सरकारी स्थिर निवेशों (फिक्स्ड इन्वेस्टमेण्ट) में भी वृद्धि हो जाय । निर्यात-योग्य फालतू (सरप्लस) माल की मात्रा में वृद्धि होने और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात के लिए हाल ही में किये जा रहे प्रयत्नों को देखते हुए आशा है कि निर्यात की आमदनी में भी काफी वृद्धि हो सकेगी ।

सारणी—1

उत्पादन और आमदनी में परिवर्तन

मद	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68
	(पहले के वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत परिवर्तन)			
1. स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय	7.4	−4.8	1.7	(10.8)
2. कृषि-उत्पादन	10.8	−16.3	−0.2	(20)
3. अन्य-उत्पादन	10.0	−19.5	3.1	(27)
4. औद्योगिक उत्पादन	5.8	4.0	2.8	1.7*
(i) खान-खुदाई और पत्थर-खुदाई	−2.5	10.3	1.4	1.1*
(ii) वस्तु-निर्माण	6.1	3.1	2.5	1.0*
(iii) बिजली-उत्पादन	11.5	10.5	9.2	11.0*
5. रेलों द्वारा ले जाये गये यात्री-किलोमीटर	5.5	3.0	6.1	उपलब्ध नहीं
6. रेलों द्वारा ले जाये गये मेट्रिक टन-किलोमीटर	−0.3	9.6	−0.2	—तदेव—
7. सरकारी क्षेत्र में नियोजन	5.9	4.5	2.9	2.5†

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्थूल अनुमानों के हैं जो उस समय उपलब्ध सूचना पर आधारित हैं।

* अप्रैल-अक्टूबर 1966 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 1967 की अवधि के आंकड़े।

† जून 1966 के अन्त की तुलना में जून 1967 के अन्त के आंकड़े।

4. अगले विभागों में आर्थिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, हाल की घटनाओं और नीति सम्बन्धी परिवर्तनों को वास्तविक पृष्ठभूमि में विचार किया गया है। विभाग II में शस्य की उपलब्धि में होने वाली घटबढ़, कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने और अन्न का वितरण करने के नीति सम्बन्धी उपायों और कृषि सम्बन्धी सम्भावनाओं पर विचार किया गया है। विभाग III में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति के धीमी हो जाने और उसे फिर से तेज करने के उपायों का विश्लेषण किया गया है। विभाग IV मुद्राबाहुल्य के नियन्त्रण के सम्बन्ध में और विभाग V शोधन-सन्तुलन और विदेशी सहायता के सम्बन्ध में है। अंत में संक्षिप्त मूल्यांकन किया गया है।